RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

INDORE 25 JANUARY TO 31 JANUARY 2023 प्रति बुधवार वर्ष 08 अंक 19 पृष्ठ 8 कीमत 5 रु.

Inside News

दावोस में पूरी दुनिया ने देखा भारतीय अर्थव्यवस्था का दमखम! Page 2

आजादी के बाद से अब तक कैसा रहा डॉलर के मुकाबले रुपये का सफर? Page 3

टाटा मोटर्स ने प्राइसिंग के साथ नेक्सन ईवी पोर्टफोलियो को नए अंदाज में पेश किया Page 5

editoria!

भ्रामक ज्ञान

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विकिपीडिया जैसे सूचनात्मक मंचों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। उन पर भ्रामक सूचनाएं हो सकती हैं। हालांकि अदालत ने यह बात कानूनी मामलों के मद्देनजर कही और न्यायिक अधिकारियों को ऐसे स्रोतों के उपयोग को लेकर आगाह किया है, पर इसे व्यापक संदर्भ में लेने की जरूरत है। आजकल तथ्यों के लिए विकिपीडिया जैसे मंचों पर अध्येताओं, व्यावसायिक गतिविधियों, शैक्षणिक कार्यक्रमों की निर्भरता लगातार बढ़ती गई है। ऐसे में अगर यह मंच इतना गैर-भरोसेमंद माना जा रहा है, तो यह गंभीर बात है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे मंचों के सहारे विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करते देखे जाते हैं। मगर इस हकीकत से मुंह नहीं फेरा जा सकता कि विकिपीडिया पर बहुत सारे तथ्य गलत या भ्रामक पाए जाते हैं। इसकी एक वजह स्पष्ट है कि इस मंच ने संपादन की सुविधा खुली छोड़ रखी है। कोई भी वहां जाकर तथ्यों को सुधार सकता है। तथ्यों में उलट-फेर कर सकता है। बहुत पहले इसके कई बड़े उदाहरण देखने को मिल चुके हैं। गांधीजी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसी शख्सियतों के जीवन से जुड़े अनेक भ्रामक तथ्य उन पर परोसे गए हैं। एक सामान्य अध्येता ऐसे तथ्यों को पकड़ नहीं पाता और उसके मन में कई तरह के दुराग्रह पनप सकते हैं। खासकर कानूनी मामलों में अगर विकिपीडिया जैसे मंचों पर गलत और भ्रामक तथ्य परोसे जाते हैं और उनका उपयोग किसी मामले को सुलझाने के लिए किया जाता है, तो उससे आने वाले समय के लिए गलत नजीर भी बनती है। इसलिए कानून की अधिकृत पुस्तकें ही इस मामले में प्रामाणिक मानी जानी चाहिए। लेकिन आज जिस तरह युवा पीढ़ी पढ़ाई-लिखाई को लेकर इंटरनेट पर निर्भर होती गई है। वह अपनी हर जिज्ञासा को लेकर तुरंत इंटरनेट खंगालना शुरू कर देती है, खासकर विकिपीडिया जैसे ज्ञानकोश पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेती है, उसे खतरनाक नतीजे भी भुगतने पड़ सकते हैं। उस पर भरोसा करके अगर उसने किसी सवाल का गलत जवाब दे दिया, जो अधिकृत पुस्तक में छपे तथ्य से मेल नहीं खाता, तो उसे नुकसान हो सकता है। जिन प्रतियोगी परीक्षाओं में ऋणात्मक मूल्यांकन की व्यवस्था है, उनमें भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस तरह सर्वोच्च न्यायालय की ताजा टिप्पणी को गंभीरता से लेने की जरूरत है। यह सही है कि प्रामाणिक पुस्तकों का विकल्प दूसरा कोई माध्यम नहीं हो सकता, पर पिछले कुछ सालों में जिस तरह इंटरनेट एक सशक्त शिक्षा माध्यम के रूप में उभरा है, उसमें ज्ञान की दुनिया का खासा विस्तार हुआ है। पीडीएफ रूप में और किंडल आदि पर पुस्तकें पढ़ने की सुविधा उपलब्ध है। तमाम शैक्षणिक संस्थान अपनी पाठ्य और सहायक पुस्तकें इंटरनेट पर डालते हैं। ई-पाठशाला जैसी व्यवस्थाएं हैं। मगर इसके समांतर इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे मंच सक्रिय हैं, जो बड़े पाठक समुदाय को आकर्षित करने और लाभ कमाने के लोभ में चल रहे हैं। उन पर परोसी जाने वाली बहुत सारी सामग्री अपुष्ट और अप्रामाणिक है। इसे रोकने की जरूरत लंबे समय से रेखांकित की जा रही है। किसी भी माध्यम से गलत तथ्य और भ्रामक जानकारियां उपलब्ध कराना एक प्रकार का अपराध है। मगर इसके लिए कोई कड़ी कार्रवाई न होने की वजह से ऐसे अधकचरे मंच खूब फल-फूल रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद यह बात रेखांकित हुई है कि ऐसे मंचों, सूचना के स्रोतों पर नजर रखने और उन्हें अनुशासित बनाने के लिए एक नियामक तंत्र होना ही चाहिए।

ग्लोबल मंदी की चिंता ने बनाया कच्चे तेल में दबाव

लगातार 5वें हफ्ते अमेरिका में क्रूड इन्वेंटरी बढ़ी

नई दिल्ली। एजेंसी

ग्लोबल मंदी की चिंताओं से कच्चे तेल में गिरावट आई है। ळए मैन्युफैक्चरिंग के कमजोर आंकड़ों से भी कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। लगातार 7वें महीने ळए में बिजनेस एक्टिविटी गिरी है। ग्लोबल मंदी और मांग में कमजोरी की आशंका बढ़ी है। कच्चे तेल की तेजी पर ब्रेक लगा है। कच्चे तेल का भाव कल 2 फीसदी गिरा है। ब्रेंट का भाव 87 डॉलर के नीचे फिसला है जबकि 23 जनवरी को ब्रेंट $89 के पार था। वहीं WTI में भी ₹81 के नीचे कारोबार कर रहा । जबकि एमसीएक्स पर कच्चा तेल 6600 के करीब नजर आ रहा है। ग्लोबल मंदी की चिंताओं से कच्चे तेल में गिरावट आई है। ळए मैन्युफैक्चरिंग के कमजोर आंकड़ों से भी कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। लगातार 7वें महीने ळए में बिजनेस एक्टिविटी गिरी है। ग्लोबल मंदी और मांग में कमजोरी की आशंका बढ़ी है। वहीं लगातार 5वें हफ्ते अमेरिका में क्रूड इन्वेंटरी बढ़ी है।

इस बीच अमेरिकी एनर्जी इनफार्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के आधिकारिक आंकड़े बुधवार को जारी किए जाएंगे। उम्मीद है कि चीन की फ्यूल डिमांड साल की दूसरी रिकवर हो जाएगी और मार्केट सेंटीमेंट को सपोर्ट करेगी। एक्सपर्ट ने आने वाले हफ्तों में WTI क्रूड के $75 और $85 प्रति बैरल के बीच कारोबार करने का अनुमान लगाया है।

ऑल टाइम हाई पर पहुंचा गोल्ड

इस बीच शर्ें पर सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंचा है। शर्ें पर सोने में 56900 के पार कारोबार कर रहा है। कल MCX पर सोने की ऊंचाई 57125 थी जबकि COMEX पर सोना 9 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा । सोना COMEX पर $1932 के पार निकला है वहीं चांदी 24 डॉलर के करीब कारोबार कर रहा है। एमसीएक्स पर चांदी 68500 के करीब कारोबार कर रहा है। डॉलर में कमजोरी से सोने की कीमतों में तेजी आई है। डॉलर इंडेक्स 101.66 के स्तर तक लुढ़का है। लगातार 10वें दिन डॉलर 102 के नीचे कायम है। फेड के रुख में नरमी की उम्मीद से भाव चढ़े है । 1 फरवरी को US में 0.25% बढ़ने की उम्मीद है।

ब्रेंट क्रूड फिसलकर 86 डॉलर पर

नई दिल्ली। एजेंसी

ब्रेंट क्रूड की कीमतों में कमजोरी देखने को मिली है। क्रूड बीते 24 घंटों में इंटरनेशनल मार्केट में 2.3 फीसदी फिसलकर 86 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। क्रूड 24 जनवरी को 89 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचा था। अमेरिकी क्रूड भी नरमी के साथ 80 डॉलर प्रति बैरल के करीब है। दूसरी ओर घरेलू ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 25 जनवरी 2022 को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये है, जबकि 1 लीटर डीजल 89.62 रुपये का बिक रहा है। देश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान के श्रीगंगानगर में है। जबकि सबसे सस्ता पेट्रोल पोर्ट ब्लेयर में 84.10 रुपये प्रति लीटर है। इस साल अप्रैल के बाद से पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी नहीं हुई है। हालांकि 22 मई को सरकार ने पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी का फैसला किया, जिससे कीमतें कम हुई थीं।

बजट 2023 में टैक्सपेयर्स और वेतनभोगियों को मिलेगी राहत?

नई इनकम टैक्स व्यवस्था में हो सकता है बदलाव

नई दिल्ली। एजेंसी

लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सरकार का आखिरी केंद्रीय बजट टैक्सपेयर्स और वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आ सकता है। पिछले कुछ बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं करने की घोषणा के बाद सरकार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव का कर सकती है। 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई आयकर व्यवस्था लागू की थी। उम्मीद है इस बार इसे और अधिक आकर्षक बनाने का ऐलान कर सकती हैं। जबकि नई आयकर व्यवस्था में टैक्स राशि कम है लेकिन इसमें कोई छूट लाभ नहीं है। इस वजह से बहुत कम लोगों से इसे स्वीकार किया है। इसे देखते हुए मोदी सरकार नई टैक्स व्यवस्था को और आकर्षक बनाने पर काम कर रही है और ईटी नाउ को पता चला है कि वित्त मंत्रालय इस व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करने की योजना बना रहा है। सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि मंत्रालय टैक्स योग्य आयकर छूट की मौजूदा सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए कर सकता है।

नई इनकम टैक्स व्यवस्था संरचना में परिवर्तन

नई टैक्स व्यवस्था के तहत 20 लाख रुपए तक की टैक्स योग्य आय वाले व्यक्तियों के लिए टैक्स की सीमा 20 प्रतिशत रखने की सिफारिश की जा रही है। यह कदम योजना में और अधिक लेने वालों को आमंत्रित कर सकता है। जिसने अभी तक निराशाजनक प्रतिक्रिया दी है। पूर्व-बजट परामर्श के दौरान कई उद्योग निकायों द्वारा सिफारिशें की गईं। इसके पीछे एक और तर्क यह है कि अगर छूटों को हटाकर टैक्स स्लैब घटाए जाते हैं और टैक्सपेयर्स छूट वाली नई व्यवस्था को अपनाते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी। पुरानी इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत, 7.5 लाख रुपए तक की टैक्स योग्य इनकम टैक्स मुक्त होता है। जब छूट को भी ध्यान में रखा जाता है।

दावोस में पूरी दुनिया ने देखा भारतीय अर्थव्यवस्था का दमखम!

भारत के आगे चीन की चमक पड़ी फीकी

नई दिल्ली। एजेंसी

स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की सालाना बैठक 20 जनवरी 2023 को समाप्त हो गई। पांच दिन चली इस बैठक में जलवायु, युद्ध और आर्थिक मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत ने अपना दमखम दिखाया है। साल 2023 में, जैसा कि वैश्विक मंदी की आशंका बनी हुई है। देश को किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, विश्व बैंक संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए केवल 0.5ज्ञ और चीन के लिए 4.3ज्ञ की तुलना में 6.6ज्ञ की वृद्धि का अनुमान लगा रहा है। अगर भारत अपनी गति को बनाए रख सकता है, तो भारत 2026 में जर्मनी को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पीछे छोड़ देगा। साल 2032 में जापान को नंबर तीन स्थान से पछाड़ देगा और 2035 तक 10 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ केवल तीसरा देश बन जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है, जो इसे दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाती है। डब्ल्यूईएफ के संस्थापक और कार्यकारी चेयरमैन क्लॉस श्वाब ने कहा कि एक बंटी हुई दुनिया में भारत एक उज्ज्वल स्थान है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व व्यवस्था में एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभर रहा है।

भारत से सौ नेताओं ने लिया हिस्सा

पांच दिवसीय बैठक में लगभग 100 भारतीय नेताओं ने भाग लिया, जिनमें चार केंद्रीय मंत्री और एक मुख्यमंत्री शामिल थे। डब्ल्यूईएफ के अध्यक्ष बोर्गे ब्रेंड ने अपनी समापन टिप्पणी में कहा कि जलवायु मोर्चे पर कदम और न्यायसंगत वृद्धि लक्ष्यों पर महत्वपूर्ण प्रगति के साथ यह एक उल्लेखनीय सप्ताह रहा है। सोमवार को शुरू हुई इस बैठक में कई राष्ट्राध्यक्षों या सरकार के प्रमुख शामिल हुए और विभिन्न बैठकों को संबोधित किया। साथ ही बड़ी संख्या में राजनीति, उद्योग, शिक्षा और नागरिक समाज के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस बार की बैठक का विषय 'एक खंडित दुनिया में सहयोग' था। ब्रेंड ने कहा कि दुनिया भले ही आज खंडित हो, लेकिन यहां उम्मीदें उभरी हैं, ताकि कल ऐसा न हो। आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने समापन सत्र के दौरान कहा कि वैश्विक नेताओं के लिए उनका संदेश व्यावहारिकता और सहयोग का है।

वैश्विक जीडीपी में आ सकती है 7 फीसदी की गिरावट

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) की प्रमुख क्रिस्टलीना जॉर्जीवा ने शुक्रवार को विश्व समुदाय से व्यावहारिक एवं सहयोग पूर्ण रुख का अनुरोध करते हुए कहा कि आपस में विभाजित होने से वैश्विक जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में सात प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है। जॉर्जीवा ने विश्व आर्थिक मंच की यहां आयोजित 53वीं बैठक के अंतिम दिन के सत्र को संबोधित करते हुए कहा, 'अगर हम अब भी एकजुट नहीं हुए तो हमें अर्थव्यवस्था एवं लोगों की बेहतरी के लिए बड़े जोखिम का सामना करना होगा।' उन्होंने कहा कि अगर मध्यम अवधि की वृद्धि संभावनाओं को देखें तो आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े मसलों को हल करने का तरीका हमारी वृद्धि संभावनाओं को निर्धारित कर देगा। उन्होंने कहा, 'दुनिया के लिए मेरा संदेश यही है कि हम व्यावहारिक और सहयोग करने वाले बनें।' वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में सुधार की संभावना के बारे में पूछे जाने पर आईएमएफ प्रमुख ने कहा, 'पिछले साल हमने वृद्धि अनुमानों को तीन बार संशोधित किया था और इसमें आगे और कमी न करना ही फिलहाल के लिए अच्छी खबर है।'उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में श्रम बाजार की स्थिति पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है।

भारत बन सकता है डाटा सेंटर का मैगनेट, वित्त मंत्री से ये हैं उम्मीदें

एजेंसी

कोरोना वायरस महामारी के चलते देश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन बावजूद इसके भारत की आर्थिक विकास दर पिछले कुछ सालों में स्थिर रही है। पिछले साल हमारे देश ने आजादी के 75 साल और अब तक की उपलब्धियों का उत्सव मनाया। भारत ने घ्र्रें100 की ओर एक यात्रा भी शुरू की है, जिसका उद्देश?य 2047 तक देश को और अधिक समृद्ध अर्थव्यवस्था बनाना है। अगले 25 सालों के लिए अमृत काल के इस चरण में, कई क्षेत्र देश के विकास में सक्रिय रूप से योगदान देंगे और इन्हीं में तकनीक उद्योग देश के आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए तैयार है। यह डाटा सुरक्षा बिल, साइबर सुरक्षा की दृष्टिकोण से और और डाटा सेंटर उद्योग में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करेगा ।

एशिया प्रशांत क्षेत्र में हमारा देश धीरे-धीरे डाटा सेंटर्स के लिए राजधानी के रूप में उभर रहा है, साथ ही एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए डाटा सेंटर्स की मांग की पूर्ति करेगा । इसके अलावा, कई बहुराष्ट्रीय हाइपरस्केलर विशाल डाटा सेंटर बनाकर और डाटा होस्ट कर उद्योग को आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल, व्ध्ध ने कहा है कि 2022-2024 के दौरान मौजूदा और नए खिलाडियों द्वारा क्षमता विस्तार के परिणामस्वरूप 804 ऐं की अतिरिक्त क्षमता होने की उम्मीद है। डाटा सेंटर को अब आधारभूत संरचना का दर्जा दिए जाने के साथ, भारतीय स्वामित्व वाले डाटा सेंटर्स को समर्थन मिलना चाहिए। हम आगामी बजट में भूमि, निर्माण, यांत्रिक और प्लंबिंग लागत से संबंधित प्रोत्साहन या पूंजी सब्सिडी देखने की उम्मीद करते हैं। इसके अतिरिक्त, बिना रुकावट बिजली सप्लाई और कनेक्टिविटी सुनिश्चित होने से डाटा सेंटर उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है ।

सरकार को स्थानीय नीति के लिए लोकल के तहत स्वदेशी डाटा सेंटर लाने पर विचार करना चाहिए। सरकारी निकायों को विशेष रूप से भारतीय स्वामित्व वाले डाटा सेंटर का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और निजी क्षेत्र की संस्थाओं को स्थानीय स्वामित्व वाले डाटा सेंटर का उपयोग करने के लिए विशेष छूट मिलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, हम बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश?योरेंस, दूरसंचार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), हेल्थकेयर और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में अपने ऑटोमेशन प्रयासों को बढ़ाने वाले संगठनों में बढ़ोतरी देख रहे हैं। इंट्रीग्रेटेड ऑटोमेशन विशेष रूप से लोगों, प्रक्रियाओं और टेक?नोलॉजी में एकीकरण प्रदान करता है और केंद्रित उद्देश्य और परिवर्तन प्रबंधन द्वारा निर्देशित होता है। यह बिजनेस को परिचालन पर ध्यान केंद्रित करने और मशीनों पर सांसारिक कार्यों को छोड़ने की अनुमति देता है। इस तरह से यह व्यवसाय के तेजी से विस्तार में सहायता करता है। कुल मिलाकर यह आर्थिक विकास में योगदान देगा और हम आशा करते हैं कि इस क्षेत्र को आगामी बजट में शामिल किया जाएगा। सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन को प्रत्यक्ष रूप से आगे बढ़ाने वाले और सभी क्षेत्रों में डिजिटल परिवर्तन यात्रा में सहायता करने वाले निजी खिलाड़ियों को भी पूंजी सब्सिडी यानी पूंजीगत मदद, कर लाभ आदि के रूप में अतिरिक्त प्रोत्साहन की पेशकश की जानी चाहिए। हमें 2047 तक एक नए डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यबल की आवश्यकता होगी। हमें शिक्षा क्षेत्र में निवेश की उम्मीद है और शैक्षणिक पाठ्यक्रम में कौशल बढ़ाने पहल भी देखने की उम्मीद करते हैं, जो डिजिटल आंदोलन को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार इस इंडस्?ट्री 4.0 रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए सही दिशा में कदम उठाएगी और भारतीय उद्योग जगत की एक ठोस सहयोगी बनेगी। और साथ मिलकर देश एक नई सफलता की कहानी लिख सकता है।

इनकम टैक्स बचाने के लिए 31 मार्च से पहले जरूर कर लें ये काम

बचत के साथ मिलेगा तगड़ा रिटर्न

नई दिल्ली। एजेंसी

अगर आपने अब तक फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो 31 मार्च से पहले कुछ काम जरूर कर लें। जब इनकम बढ़ती है तो टैक्स का डर सताने लगता है। इनकम पर सरकार टैक्स लगाती है जो तय सीमा से ज्यादा आमदनी होने पर देना होता है। लेकिन इनकम टैक्स ऐक्ट में यह प्रावधान भी है कि हम कुछ स्कीम में पूंजी को निवेश करके टैक्स में कुछ छूट पा सकते हैं। इससे हमें थोड़ी-सी राहत मिल जाती है। इन्हें टैक्स सेविंग स्कीम कहा जाता है। यह निवेश कुछ अप्रूव्ड स्कीम्स पर ही हो सकता है, जैसे पीपीएफ, ईपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ईएलएसएस, एनएससी, होम लोन, ट्यूशन फीस आदि। वैसे हम हमेशा ऐसे निवेश की तलाश में करते हैं, जहां अच्छे रिटर्न मिल सकें। यहां हम आपको एक ऐसी ही स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं। जिसमें आप निवेश करके अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं।

इन बातों का रखें ध्यान

निवेश को अपने लक्ष्य से जोड़ सकते हैं। जैसे रिटायरमेंट के बाद कुछ मंथली इनकम के लिए एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान चुन सकते हैं

इक्विटी पोर्टफोलियो में अलग-अलग तरह के शेयर होते हैं जो प्रोफेशनल फंड मैनेजरों द्वारा उनकी हर तरह की परफार्मेंस के आधार पर चुने जाते हैं

ईएलएसएस इमोशन फ्री निवेश होता है। टैक्स बचाने के साथ ही निवेश भी हो जाता है। यह प्रॉपर्टी या गोल्ड जैसा निवेश नहीं है

ईएलएसएस में हर महीने भी निवेश कर सकते हैं यानी इसमें बचत करना फ्लैक्सिबल होता है। कभी भी खरीद सकते हैं चाहे मार्केट डाउन हो या अप

इस स्कीम में कर सकते हैं निवेश

आप ईएलएसएस में निवेश कर सकते हैं। ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होते हैं। इक्विटी यानी शेयर बाजार, इसका मतलब यह हुआ कि हम अपना पैसा सीधे शेयर बाजार में न लगाकर इन म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं। इसके बाद ये फंड हमारे द्वारा निवेश की गई रकम का अधिकांश हिस्सा शेयर बाजार में लगा देते हैं। यह करीब 80 फीसदी हो सकता है। इनकम टैक्स ऐक्ट 1961 के सेक्शन 80सी के तहत हम ईएलएसएस में निवेश करके एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम डेढ़ लाख रुपये निवेश पर 46 हजार 800 रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं। इसलिए अगर टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश करना है तो ईएलएसएस बेहतर विकल्प है। इसके तीन बड़े फायदे भी हैं। पहला, हमारे पैसों की बचत होती है। दूसरा टैक्स छूट का फायदा मिलता है। तीसरा, इसमें निवेश से रिटर्न बढ़िया मिलता है।

ईएलएसएस में ऐसे करें निवेश

अगर आप ईएलएसएस में निवेश करना चाहते हैं तो आपको अपने बैंक, फाइनेंशियल एडवाइजर या ऑनलाइन म्यूचुअल फंड देने वाले प्लेटफार्म से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंडस में कितना पैसा निवेश करना है इसका फैसला फंड की पिछली परफार्मेंस देखकर नहीं करना चाहिए। अगर किसी एडवाइजर की मदद लेंगे तो वे सभी जोखिमों को ध्यान में रखते हुए सही सलाह दे सकते हैं। इसमें निवेश करने के लिए डायरेक्ट प्लान या रेग्युलर प्लान लिया जा सकता है। डायरेक्ट प्लान में स्कीम का चुनाव खुद कर सकते हैं और रेग्युलर प्लान में एडवाइजर की मदद लेनी होती है।

कितना मिल सकता है रिटर्न

ईएलएसएस बाजार में लिंक्ड होने की वजह से इससे हमेशा एक जैसा रिटर्न नहीं मिलता है। कभी रिटर्न कम हो सकता है और कभी ज्यादा। यह भी हो सकता है कि रिटर्न नेगेटिव हो जाए। इसलिए सिर्फ 3 साल के लिए निवेश करने पर कितना फायदा होगा यह नहीं कहा जा सकता है। लेकिन लंबे समय के लिए निवेश करने पर फायदा ज्यादा होने की संभावना बढ़ जाती है। एक्सपर्ट कहते हैं कि 5 साल से ज्यादा वक्त तक निवेश करने पर 12 से 15 फीसदी तक का रिटर्न आसानी से मिल सकता है। हालांकि कुछ टॉप के फंड 30 फीसदी तक भी रिटर्न दे चुके हैं। वैसे ध्यान रखें की रिटर्न की कोई भी गारंटी नहीं होती है।

आजादी के बाद से अब तक कैसा रहा डॉलर के मुकाबले रुपये का सफर?

नई दिल्ली। एजेंसी

अमेरिका को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ ही अमेरिकी करेंसी डॉलर की भी तूती बोलती है। डॉलर को दुनिया का सबसे ताकतवर करेंसी भी माना जाता है। हर देश दूसरे देशों के साथ व्यापार डॉलर में ही करते हैं। निवेशक डॉलर में किसी देश में निवेश करते हैं। डॉलर को बेंचमार्क करेंसी माना जाता है और डॉलर दुनिया की दूसरी करेंसी का वैल्यू भी तय करती है। ठीक इसी प्रकार रुपये की तुलना भी डॉलर के वैल्यू के साथ की जाती है।

1947 में एक डॉलर का वैल्यू 4.16 रुपये

1947 में आजादी मिलने के बाद भारतीय करेंसी को डॉलर के साथ मापने की शुरुआत हुई जो पहले ब्रिटिश राज होने के चलते

कब आई रुपये में बड़ी गिरावट?

पाउंड में किया जाता था। 1947 में एक डॉलर का वैल्यू रुपये के मुकाबले 4.16 रुपये हुआ करता था। 1950 से लेकर 1966 तक एक डॉलर कै वैल्यू 4.76 रुपये बना रहा। लेकिन इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट, विदेशों से लिए गए कर्ज, 1962 में भारत-चीन युद्ध, 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध और 1966 में आए भीषण सूखे के कारण 1967 में एक डॉलर का वैल्यू 7.50 रुपये के बराबर हो गया। कच्चे तेल की सप्लाई के संकट के चलते 1974 में एक डॉलर का वैल्यू घटकर 8.10 रुपये पर आ गया। इसके बाद देश में राजनीतिक संकट, भारी भरकम विदेशी कर्ज लेने के चलते करेंसी में बड़ी गिरावट देखने को मिली जिसके बाद अगले एक दशक में लगातार डॉलर के मुकाबले रुपये गिरता रहा जो 1990 में 17.50 रुपये के लेवल पर आ गया।

1990 के बाद रुपये में बड़ी गिरावट का सिलसिला

1990 में भारतीय अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल छाए हुए थे। भारत पर विदेशी कर्ज का बड़ा बोझ था। सरकार को जितना रेवेन्यू आ रहा था उसका 39 फीसदी कर्ज के ब्याज के मद में भुगतान करना पड़ रहा था। सरकार का वित्तीय घाटा 7.8 फीसदी पर जा पहुंचा था। भारत डिफाल्टर घोषित किए जाने के कगार पर जा पहुंचा था। 1991 में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। 1992 में एक डॉलर के मुकाबले रुपये का वैल्यू गिरकर 25.92 रुपये पर जा गिरा। 2004 में यूपीए जब सत्ता में आई तब एक डॉलर का वैल्यू 45.32 रुपये हुआ करता था। 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई उसके एक साल बाद एक डॉलर का वैल्यू 63 रुपये था। लेकिन उसके बाद से भी रुपये में कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। 2021 में एक डॉलर का वैल्यू 74.57 रुपये के बराबर था।

2022 में रुपये में आई कमजोरी

2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले, बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ाने का सिलसिला शुरू किया

जिसके बाद विदेशी निवेशक अपना निवेश वापस निकालने लगे। जिसके बाद एक डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी तो आई ही साथ में भारत का विदेशी मुद्रा कोष जो 640 अरब डॉलर के ऊपर जा पहुंचा था वो घटकर 530 अरब डॉलर तक घट गया। 2022 में एक समय डॉलर के मुकाबले रुपये में 10 फीसदी की गिरावट आ गई थी। एक डॉलर के मुकाबले रुपये का वैल्यू घटकर 83 के लेवल तक जा गिरा। फिलहाल एक डॉलर के मुकाबले रुपये का वैल्यू 81.71 रुपये के करीब है।

मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में किसान उत्पादक संगठनों को मज़बूत करने के लिए वॉलमार्ट फाउंडेशन का 35 लाख डॉलर का निवेश

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

वॉलमार्ट फाउंडेशन ने मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) ढांचे के माध्यम से छोटे किसानों के सशक्तिकरण के उद्देश्य के लिए तीन नए अनुदानों की घोषणा की। इस अनुदान में मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण और उनकी आय बढ़ाने के लिए ऐक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज़ को 17 लाख डॉलर, मध्य प्रदेश में छोटे और सीमांत किसानों के जीवन में सुधार लाने और महिलाओं को ग्रामीण उद्यमियों के तौर पर आगे बढ़ाने के लिए सृजन को 10.9 लाख डॉलर और मध्य प्रदेश में छोटे किसानों के लिए जीवनयापन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ऐक्शन फॉर सोशल एडवांसमेंट (एएसए) को 11 लाख डॉलर दिए जाएंगे। उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट 39 एफपीओ और 60,000 से ज़्यादा छोटे किसानों तक पहुंचेंगे। जूली गेहरकी, वाइस प्रेसिडेंट एवं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, वॉलमार्ट फाउंडेशन ने कहा, 'बीते वर्षों के दौरान वॉलमार्ट फाउंडेशन ने भारत में अपने सहयोगियों के माध्यम से छोटे किसानों के जीवनस्तर में सुधार करने और उनके जीवनयापन को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया है। हमने 2018 से इसके लिए 2.5 करोड़ डॉलर से ज़्यादा निवेश किया है। वॉलमार्ट फाउंडेशन से मिले अनुदान के माध्यम से, ऐक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज़ 'उड़ान-फ्लाइट आउट ऑफ पावर्टी' को लागू कर सकेगी जिसका उद्देश्य एफपीओ को सशक्त बनाकर और समावेशी मूल्य श्रृंखला स्थापित कर 12,000 छोटे किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 20 एफपीओ को क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा। वर्ष 2018 में वॉलमार्ट फाउंडेशन ने भारत में छोटे किसानों की मदद करने के लिए पांच वर्षों की अवधि में 2.5 करोड़ डॉलर निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई थी, ताकि ऐसे किसानों की आय बढ़ाई जा सके और उनके जीवनस्तर में सुधार किया जा सके। वॉलमार्ट फाउंडेशन को उम्मीद है कि ऐक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज़, सृजन और एएसए को अतिरिक्त आर्थिक अनुदान के माध्यम से अपना समर्थन देकर वह एफपीओ ईकोसिस्टम को मज़बूती देने और छोटे किसानों के जीवन में बदलाव लाने में अपना योगदान दे सकेगा।

फ्रांस, जर्मनी, चीन और अमेरिका की जमात में शामिल होगा भारत,

देश में ही बनेंगे हवाई जहाज!

नई दिल्ली। एजेंसी

आने वाले दिनों में आपको मेड इन इंडिया विमान में सफर करने का मौका मिल सकता है। सरकार ने भारत को एयरोस्पेस इंडस्ट्री का हब बनाने के लिए बड़ी योजना बनाई है। भारत एविएशन इंडस्ट्री में बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। देश की एयरलाइन कंपनियां अगले दस साल में 2,000 विमानों का ऑर्डर दे सकती हैं। सरकार चाहती हैं कि एयरबस और बोइंग जैसी दिग्गज कंपनियां भारत में ही विमान तैयार करें। सरकार ने इस बारे में इन कंपनियों से बात भी की है और उनके जवाब का इंतजार है। हाल के वर्षों में एयरक्राफ्ट और टर्बो जेट्स के आयात में भारी तेजी आई है। सरकार ट्रेड डेफिसिट में कमी लाने के लिए ऐसी चीजों की पहचान कर रही है, जिनका बहुत ज्यादा आयात किया जा रहा है। देश में मिडिल क्लास की आबादी तेजी से बढ़ रही है। इस वर्ग के लिए हवाई जहाज से यात्रा करना अब लग्जरी नहीं रह गया है बल्कि यह उसकी जरूरत बन गई है। यही वजह है कि घरेलू एयरलाइन कंपनियां तेजी से अपने बेड़े का विस्तार कर रही हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने 2019 में 320 नियो किस्म के विमानों का ऑर्डर दिया था। उसके बेड़े में अभी ऐसे 730 विमान हैं। टाटा ग्रुप भी बड़ा ऑर्डर देने की तैयारी में है। इसके अलावा कई छोटी कंपनियां भी विमानों का ऑर्डर दे सकती हैं। कुल मिलाकर अगले 10 साल में भारतीय एयरलाइन कंपनियां 2000 विमानों का ऑर्डर दे सकती हैं।

इंपोर्ट में भारी तेजी

एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनियां भारत से भी कुछ कलपुर्जे खरीद रही हैं। लेकिन सरकार इससे संतुष्ट नहीं है। वह चाहती है कि बोइंग और एयरबस भारत में अपनी फाइनल एसेंबली लाइन स्थापित करें। पिछले महीने कॉमर्स डिपार्टमेंट ने देश में एयरक्राफ्ट्स के बढ़ते आयात पर अलर्ट जारी किया था। अप्रैल-सितंबर के दौरान देश में एयरक्राफ्ट्स के आयात में 56.5 फीसदी, टर्बो जेट्स के आयात में 34 फीसदी और हेलीकॉप्टर्स के आयात में 42 फीसदी तेजी आई। इसके बाद एविएशन मिनिस्ट्री ने ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए रणनीति बनाने का काम शुरू किया था। फाइनल एसेंबली लाइन का मतलब है कि भारत में इसका पूरा सप्लाई चेन ईकोसिस्टम होगा। इनमें एयरक्राफ्ट की बॉडी बनाने से लेकर विंग्स, एसेंबल्ड इंजन, सीट आदि शामिल है। जानकारों का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में समय लग सकता है। लेकिन इसकी शुरुआत अभी से हो जानी चाहिए ताकि अगले तीन-चार साल में यह इसका ईकोसिस्टम तैयार हो जाए। सरकार भी मानती है कि यह देश में एयरक्राफ्ट बनाने की दिशा में अगला कदम बढ़ाने का सही समय है।

कहां-कहां एयरक्राफ्ट बनते हैं

यूरोपीय कंपनी एयरबस की पूरी दुनिया में चार फैसिलिटीज हैं। ये फ्रांस के शहर ऊदल्लदले, जर्मनी के हैम्बर्ग, चीन के तियानजिन और अमेरिका के श्दंग्त में है। चीन की फैसलिटी ने 2008 में काम करना शुरू किया था और पिछले साल नवंबर में इससे पहला ए321 बनकर तैयार हुआ था। वहीं अमेरिकी कंपनी बोइंग की सारी एसेंबली लाइन अमेरिका में ही हैं। पिछले साल अक्टूबर में टाटा ग्रुप और एयरबस ने एयरफोर्स के लिए सी-295 एयरक्राफ्ट बनाने की घोषणा की थी। अब तक केवल सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स ही सेना के लिए विमान बनाती है।

2047 का भारत

राजकुमार जैन
स्वतंत्र विचारक

एक सशक्त राष्ट्र के रूप मे भारत अपनी एक नई पहचान बना रहा है जो आत्मनिर्भर होने के साथ साथ विश्व स्तर पर सम्मानित भी है। विगत दशकों में की गई प्रगति के आधार पर 2047 में हम एक ऐसे भारत की परिकल्पना कर सकते है जो न्यायसंगत, समावेशी, टिकाऊ और समृद्ध हो। जहा सभी नागरिकों को भोजन, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आवास और रोजगार के अवसरों जैसी बुनियादी जरूरते सुलभता से उपलब्ध होंगी। आगामी वर्षों में एक अग्रणी देश के रूप मे हम पर्यावरण की रक्षा करते हुए गरीबी और असमानता को कम करना चाहेंगे। सेवाओं के डिजिटलीकरण, स्मार्ट शहरों और कौशल विकास कार्यक्रमों जैसी पहलों के माध्यम से, मिशन 2047 का उद्देश्य भारत को एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना है जो अपने नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करते हुए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो।

सदियों के औपनिवेशिक शासन से लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता प्राप्त कर, 1947 में भारत ने लोकतंत्र की यात्रा के पहले पड़ाव पर कदम रखा था। हमारे नेताओं के प्रबल आशावादी होने के बावजूद उस समय यह माना जा रहा था कि अपनी विविध जनसंख्या और जटिल सामाजिक संरचना के कारण भारत में लोकतंत्र सफल नहीं होगा। लेकिन पिछले 75 वर्षों में, भारत ने यह साबित कर दिया है कि कड़ी चुनौतियों के बावजूद हम भारतवासी एक सफल लोकतंत्र को बनाए रखने में सफल रहे है। इन 75 वर्षों मे लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और मौलिक मानवाधिकारों को बरकरार रखते हुए भारत ने जो उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, वह विविध दृष्टिकोणों को अपनाने की हमारी समावेशी क्षमता का परिचायक है। इसके साथ ही यह स्वतंत्रता, सम्मान और न्याय के साथ जीने के लिए संकल्पित लोगों की दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रमाण भी है।

कहा जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र का विकास चार चरणों में हुआ है, पहले चरण में यानि जवाहर लाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक के दौर में लोगों को सिर्फ मतदान का अधिकार था, राजनीति में जनता की सक्रिय भागीदारी नहीं के बराबर थी। दूसरे चरण में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आरक्षण और उदारीकरण जैसे नए विचारों के साथ राजनीतीक विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। तीसरे चरण में मिली-जुली सरकारो का दौर आया तब हमने आशा की थी कि लोकतन्त्र मजबूत होगा और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं बल्कि स्थिति और खराब हो गई। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चौथे चरण की शुरुआत हुई और भारत एक शक्तिशाली लोकतन्त्र के रूप में विश्व पटल पर उंभरा। आज दुनिया में भारत की पहचान एक सशक्त राष्ट्र के रूप की जाती है। सारी दुनिया आज भारत की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। बीते 75 सालों में अपनी अंदरूनी समस्याओं और चुनौतियों के बीच इस देश ने ऐसा कुछ जरूर हासिल किया है, जिसे देखकर दुनिया की तमाम ताक़तें चमत्कृत है।

उदारीकरण के दौर के बाद भारत तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। आर्थिक, सैन्य एवं अंतरिक्ष क्षेत्र में हमने सफलता की बड़ी छलांग लगाई है। चुनौतियों के बावजूद हमारी आर्थिक विकास दर तेजी से बढ़ी है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है। भारतीय सेना परमाणु हथियारों से संपन्न दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। मिसाइल तकनीकी में दुनिया भारत का लोहा मान रही है। मंगल मिशन की सफलता एवं रॉकेट प्रक्षेपण की अपनी क्षमता के बदौलत अंतरिक्ष क्षेत्र में नए कीर्तमान स्थापित कर भारत इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हुआ है। सूचना प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में भी देश अग्रणी बना हुआ है। इन उपलब्धियों की बदौलत आज देश महाशक्ति बनने की कगार पर खड़ा है। दमदार नेतृत्व के तले भारत ने 'सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन' के मंत्र के साथ संरचनात्मक परिवर्तन लाने की असरदार शुरुआत की है

अब तक के इस कठिन सफर में एक देश के रूप में हम कहाँ से कहाँ पहुंचे है, 1947 में साक्षरता दर 12ङ्ग थी जो अब 75ङ्ग से आगे निकाल चुकी है, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओ के चलते लाईफ एक्सपेंटेसी (अनुमानित जीवन काल) 32 वर्ष से बढ़कर 70 से भी ज्यादा हो चला है, बेहतर आर्थिक प्रबंधन के चलते प्रति व्यक्ति आय रू. 250 से बढ़ कर रू 1.5 लाख तक पहुँच चुकी है, पहले खाद्यान की कमी के चलते लोग भूखे मरते थे, लेकिन आज हम आत्मनिर्भर होकर निर्यातक भी बन चुके है, रेलवे नेटवर्क 55 हजार किलोमीटर से बढ़कर 1 लाख 26 हजार किलोमीटर तक पहुँच चुका है, राष्ट्रीय राजमार्ग 21000 किलोमीटर से बढ़कर 136000 किलोमीटर हो चुका है, लोकसभा में महिला सदस्यों की भागीदारी 4.4 फीसदी से बढ़कर 11.8 फीसदी हुई है, ओलंपिक खेलों में अपनी भागीदारी के 121 वर्षों में सबसे अधिक मेडल जीतने का इतिहास रचा गया है, जल जीवन मिशन के तहत अब तक करीब 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचने लगा है, बजट 2022-23 में भारत की विकास दर 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया हैं।

देश की प्रगति की चर्चा देश की बेटियों के बारे में बात किए बिना अधूरी है। आज हाई स्कूल से लेकर मिलिट्री तक, लैब से लेकर खेल के मैदान तक हमारी लड़कियां अपनी अलग पहचान बना रही हैं। उनकी इस सफलता में विकसित भारत के भविष्य की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही है। इन होनहार बालिकाओ के परिवारों से हर माता-पिता को सीख लेनी चाहिए और अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का बराबर मौका देना चाहिए।

ग्रामीण भारत की बात की जाय तो आज हम अपने गांवों को तेजी से परिवर्तित होते देख रहे हैं। बीते कुछ वर्ष, गांवों तक सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने के रहे हैं। अब गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क एवं इन्टरनेट के रास्ते डेटा की ताकत पहुंच रही है। ग्रामीण परिवेश में भी डिजिटल एंटरप्रेन्योर तैयार हो रहे हैं। वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ सरकार ई-कॉमर्स प्लेटफार्म तैयार कर रही है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तृत फ़लक स्वयं सहायता समूहों के उत?पादों को देश के दूर-दराज के क्षेत्रों और विदेशों के उपभोक्ताओं से जोड़ेगा। कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिकों की क्षमता को महत्व दिया जा रहा है और हमारे वैज्ञानिक बहुत सूझ-बूझ से काम कर रहे हैं। उनकी क्षमताओं और उनके सुझावों को राष्ट्र निर्माण की नीतीयों में शामिल किया जा रहा है। इससे देश को खाद्यान सुरक्षा देने के साथ ही फल और सब्जियों का उत?पादन बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी।

हालांकि तेजी से बदलती तकनीक के दौर में यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि आजादी के 100 साल बाद 2047 में हमारा लोकतंत्र कैसा होगा। लेकिन यह निश्चित है कि वह समय आने तक भारत लोगों की कल्पना से कहीं आगे निकल चुका होगा। देश में हर स्तर पर तीव्र गति से विकास हो रहा है और यह तय है कि आने वाले समय में हम दुनिया की एक बड़ी तकनीकी और आर्थिक महाशक्ति होंगें। हम एक ऐसे देश की कल्पना कर सकते हैं जहां सभी समान हों और बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्या का नामोनिशान तक ना हो। हर किसी के पास खुशहाल जीवन जीने के समुचित साधन हों। मानव तस्करी, बाल श्रम आदि समाप्त होंगे और महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे, लैंगिक भेदभाव से परे जाकर कार्यस्थल और समाज में उनके सम्मान की सुरक्षा की गारंटी होगी। जाति, समुदाय, संप्रदाय आदि के आधार पर भेदभाव के बिना देश भर में मुफ्त आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाएगी।

आम जनता के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने हेतु निर्णय लेने की ब्लॉक चेन आधारित प्रक्रिया में सुधार हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग आम बात हो जाएगी, जेनेरेटिव आर्टिफिशीयल इंटेलिजेंस के विकास के साथ ही प्रशासनिक सेवाए पूर्णतः फेसलेस हो जाएंगी।

गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष्य पर आज हमें यह विचार करना चाहिए कि हम कैसा देश गढ़ना चाहते है। व्यापक सोच रखने वाले, मजबूत इरादे वाले, सुशिक्षित, चरित्रवान, बुद्धिमान, योग्य, सकारात्मक सोच वाले ईमानदार नागरिकों से बना एक सशक्त भारत या अयोग्य, बेईमान, कमजोर, लालची, धूर्त, अशिक्षित, आपराधिक सोच वाले भ्रष्ट नागरिकों से बना एक कमजोर राष्ट्र। आईये इस गणतन्त्र दिवस पर हम सब यह शपथ ले कि हम अपने कर्तव्य का पालन देशभक्ति की भावना से करेंगे और एक मजबूत और गौरवशाली भारत का निर्माण करेंगे, अपने बच्चो को एक अच्छा मनुष्य और उत्कृष्ठ नागरिक बनाएँगे जो आगे चलकर सशक्त भारत की नींव रखेंगे और भारत को उसका खोया हुआ गौरव पुनः लौटाकर विश्व का अग्रणी और सिरमौर देश बनाएँगे।

इन तीन तरह के पत्तों के बिजनेस से बन जाएंगे करोड़पति, डिमांड में नहीं आएगी कमी!

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

भारत में कई तरह के पत्तों का कारोबार बड़े पैमाने पर होता है। जैसे केले के पत्ते, साखू के पत्ते, पान के पत्ते। देश के कई हिस्सों में यह रोजगार का भी एक बहुत बड़ा साधन है। इन पत्तों की अलग-अलग जगहों पर जरूरत पड़ती है। इनमें 2 सबसे प्रमुख पत्ते हैं केले का और पान का पत्ता। इन पत्तों की मांग हमेशा हर सीजन में हर जगह बनी रहती है। पत्तों के कारोबार से अच्छी कमाई की जा सकती है। अगर केले के बारे में बात करें तो अभी तक भारत में सिर्फ केले के फलों का इस्तेमाल होता था । दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में केले के पत्तों में खाना भी परोसा जाता है। इसके अलावा पान के पत्तों की उत्तर और पूर्वी भारत में अच्छी मांग में रहती है। वहीं साखू के पत्ते का इस्तेमाल पहाड़ी इलाकों में केले के पत्ते की तरह किया जाता है।

केले के पत्ते

केले के पत्तों को पूजा में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिए पैसे भी कमाए जा सकते हैं। केले के पत्तों से प्लेट्स बनाई जाती है। दक्षिण भारत में तो लोग इसमें खाना भी खाते हैं। ऐसे में इसकी मांग में इजाफा बना रहता है। इसलिए वहां, इसकी मांग नहीं घटती है। आप केले के पत्ते को दक्षिण भारत में बेचकर बंपर कमाई कर सकते हैं। इससे एक वर्ग को रोजगार भी मिला हुआ है। यहां एक फायदा यह भी है कि पत्ते की खेती में आपकी कोई लागत नहीं है। लागत का पैसा केले की बिक्री से निकल आएगा। इसलिए यहां आपको डबल मुनाफा होगा।

साखू का पत्ता

साखू का पेड़ आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। लेकिन यह उत्तर भारत के लगभग सभी जंगलों में पाया जाता है। यह काफी लंबा होता है और इसके पत्ते चौड़े होते हैं। इसकी लकड़ी भी काफी महंगी बिकती है। इसके पत्ते से लेकर जड़ तक काफी महंगे बिकते हैं। साखू के पत्ते को तोड़कर शादी में भी इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही खाना खाने और कई तरह के सामान बनाने में भी इस्तेमाल होता है। साखू के पत्तों से भी मोटी कमाई की जा सकती है।

पान का पत्ता

पान को अमूमन सभी लोग जानते हैं और इसका प्रयोग भी करते हैं। इसको लोग खूब खाते भी हैं। चाहे वह उत्तर हो या दक्षिण सभी जगह इस पत्ते के दीवाने हैं। पूजा के सभी कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बिना पूजा पूरी नहीं हो सकती है। इसकी खेती कई राज्यों में होती है। पान की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार सब्सिडी भी मुहैया कराती है।

G20 भारत 2023 INDIA वसुधैव कुटुम्बकम् ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मध्य प्रदेश
आज़ादी का अमृत महोत्सव
मध्यप्रदेश शासन

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

प्रदेशवासियों को

74 वें

गणतंत्र दिवस पर

हार्दिक शुभकामनाएं

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

निरंतर विकास की ओर अग्रसर
मध्यप्रदेश का हर गाँव - हर शहर

D18996/22

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

आकल्पन : मध्यप्रदेश माध्यम/2023

बसंत पंचमी के दिन छात्र जरूर करें ये 5 काम, मेहरबान होगी मां सरस्वती

श्री रघुनंदन जी
9009369396
ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुविद
अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन द्वारा गोल्ड मेडलिस्ट

माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है. बसंत पंचमी का पर्व शिक्षा और संगीत की देवी माता सरस्वती को समर्पित है. कहते हैं कि इस दिन माता सरस्वती की विधिवत पूजा से इंसान के जीवन में चल रहे सारे संकट मिट जाते हैं. इस साल बसंत पंचमी का त्योहार 26 जनवरी 2023 को मनाया जाएगा. ज्योतिषियों के मुताबिक, अगर किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या उसकी एकाग्रता कमजोर है तो बसंत पंचमी के दिन वास्तु के कुछ विशेष उपाय करने से बड़ा लाभ मिल सकता है.

सरस्वती की तस्वीर

बसंत पंचमी के दिन बच्चों के स्टडी रूम में माता सरस्वती का चित्र या प्रतिमा जरूर रखें. इस तस्वीर या प्रतिमा को बच्चों के ठीक सामने रखें. ऐसा करने से उनकी एकाग्रता और ज्ञान में वृद्धि होगी. उन्हें शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. आप पढ़ाई की टेबल पर भी देवी की एक छोटी सी प्रतिमा को रख सकते हैं.

इस दिशा में मुख करके पढ़ें

पढ़ाई करते वक्त बच्चों का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए. साथ ही, ख्याल रखें कि आपकी रीढ़ एकदम सीधी रहे. बसंत पंचमी के दिन से ही इस नियम को अपने जीवन में उतार लें. निश्चित ही आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे.

पढ़ाई की टेबल

स्टडी रूम में सुनिश्चित करें कि पढ़ाई की टेबल दीवार से एकदम न चिपकी हो. दोनों के बीच पर्याप्त खाली जगह होना जरूरी है. अगर ऐसा नहीं है तो बसंत पंचमी के दिन स्टडी रूम में यह बदलाव अवश्य कर लें. शिक्षा के मोर्चे पर आप कभी असफल नहीं होंगे.

नौकरी की तैयारी

यदि आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहें तो हमेशा उत्तर दिशा में बैठकर ही पढ़ें. यह वास्तु टिप्स आपको पेशेवर जीवन में एक अच्छी नौकरी खोजने की दिशा में कभी नाकाम नहीं होने देगा.

पढ़ाई की टेबल

पढ़ाई-लिखाई में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए स्टडी टेबल से जुड़े बदलाव भी जरूरी हैं. अगर

ये बदलाव आप बसंत पंचमी पर करें तो और भी उत्तम होगा. स्टडी टेबल आयताकार होनी चाहिए. उस पर किताबों का अंबार न लगा रहे. साफ-सफाई का विशेष ख्याल रखें. स्टडी रूम को भी हमेशा साफ-सुथरा रखें.

बहते जल में प्रवाहित करें चांदी के नाग-नागिन का जोड़ा, दूर होगा कालसर्प दोष

संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ
अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन
प्रदेश प्रवक्ता

आधुनिक ज्योतिष में काल सर्प दोष के बारे में विस्तार से बताया गया है और कालसर्प दोष के कारण जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि वैदिक ज्योतिष में काल सर्प दोष के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। आधुनिक ज्योतिष के मुताबिक राहु और केतु के बीच जब सारे ग्रह हों तो कालसर्प दोष होता है।

12 तरह के होते हैं कालसर्प दोष

ज्योतिष के मुताबिक कुंडली के बारह भावों में राहु-केतु की स्थिति के अनुसार कालसर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार है - अनंत, कुलिक, वासुकि, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, कर्कोटक, शंखनाद, घातक, विषाक्त, शेषनाग, कालसर्प

कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए करें ये उपाय

कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए दूध में थोड़ी मिश्री मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करना और रोज शिव तांडव स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा बहते जल में चांदी के नाग-नागिन का जोड़ा प्रवाहित करने से भी कालसर्प दोष दूर होता है। चांदी से बनी सर्प के आकार की अंगूठी मध्यमा अंगुली में शनिवार को धारण करने से भी कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा शनिवार एवं मंगलवार को राहु एवं केतु के बीज मंत्र का जाप एक माला करके पक्षियों को जौ के दाने खिलाएं। काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए त्र्यंबकेश्वर या महाकालेश्वर जाकर शांति पूजा की जाती है।

ओपल या हीरा रत्न धारण करें

काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए रत्न शास्त्र में भी उपाय बताए गए हैं। कालसर्प योग से मुक्ति के लिए हीरा धारण करना शुभ माना जाता है। हीरा धारण करने से काल सर्प दोष के प्रभावों में कमी आती है। हालांकि हीरा महंगा होने के कारण कई लोग इसे धारण नहीं कर पाते हैं, ऐसे में इसके स्थान पर ओपल रत्न भी धारण कर सकते हैं।

बसंत पंचमी पर मां सरस्वती को लगाएं ये भोग, धन-समृद्धि में खूब होगी वृद्धि

माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन ज्ञान, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती की विधिवत पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि इस दिन मां सरस्वती प्रकट हुई थीं। इस साल बसंत पंचमी का पर्व 26 जनवरी को मनाई जा रही है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जानते हैं। बसंत पंचमी के दिन अक्षर अभ्यास, विद्या आरंभ आदि संस्कार किए जाते हैं। इस दिन मां सरस्वती की विधिवत पूजा करने के साथ कुछ खास चीजों का भोग लगा सकते हैं। इससे मां सरस्वती प्रसन्न होकर सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं।

राजभोग

मां सरस्वती की पूजा में पीली ही वस्तुओं का इस्तेमाल करना शुभ माना जाता है। ऐसे में आप चाहे, तो मां सरस्वती को राजभोग का भोग लगा सकते हैं। इससे मां जल्द प्रसन्न हो जाएगी।

बूंदी

माना जाता है कि मां सरस्वती को बूंदी अतिप्रिय है। इसलिए बसंत पंचमी के मां सरस्वती को पीली बूंदी का भोग लगा सकते हैं। आप चाहे तो बूंदी के लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं।

बेसन के लड्डू

मां सरस्वती को बेसन के लड्डू भी अति प्रिय है। इस मिठाई को भावना का प्रतीक माना जाता है। इसलिए बेसन के लड्डू चढ़ाने से मां जल्द प्रसन्न हो जाएगी।

पीले मीठे चावल

बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को पीले मीठे चावल का भोग लगाने की भी परंपरा है। इन्हें मीठे केसरी भात भी कहा जाता है। इन्हें मां को भोग लगाने वह अति प्रसन्न होती है।

केसर हलवा

मां सरस्वती की पूजा में केसर हलवा चढ़ाया जाता है। इसे पारंपरिक भोग माना जाता है। मान्यता है कि मां सरस्वती को केसर हलवा का भोग लगाने से सारे कष्टों से छुटकारा मिल जाता है।

मंगलवार को लौंग का यह टोटका बना देगा आपके हर बिगड़े काम

आमतौर पर आपने लौंग का इस्तेमाल पान या गरम मसालों में होते हुए देखा होगा। लेकिन एक छोटी सी लौंग बड़े काम की चीज होती है। ज्योतिष के अनुसार लौंग से किए गए कुछ प्रयोग आपके जीवन में बिगड़े कामों को बना देते हैं। लौंग का इस्तेमाल प्राचील काल से पूजा-पाठ, तंत्र-मंत्र में होता आया है। कई बार हमारे सामने ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका कोई हल नहीं मिलता। यदि हजारों प्रयास के बाद भी हमारे काम बिगड़ रहे हैं, आपको बार-बार असफलता मिल रही है तो ऐसे समय में लौंग के इन टोटकों को अवश्य आजमाना चाहिए।

1. मंगलवार को बालाजी की प्रतिमा के समक्ष चमेली के तेल से दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलन

से पहले उसमें दो लौंग डाल दें। फिर वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा लगातार 21 मंगलवार तक करने से आपके कार्य बनने लगेंगे। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगेगी।

2.यदि आपके घर-परिवार में आर्थिक तंगी बनी हुई है। आप इसे दूर करने के लिए मंगलवार को मां लक्ष्मी को गुलाब के फूल दो लौंग के साथ अर्पित करें। उसी समय एक लाल रंग के कपड़े में 5 लौंग और 5 कौड़ियां बांधकर अपने घर या ऑफिस (व्यापार स्थल) की तिजोरी में रख दें। आपके जीवन से आर्थिक संकट दूर होने लगेगा।

आचार्य संतोष भार्गव
ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

3.मंगलवार को आप जब किसी कार्य के लिए घर से बाहर निकलें तो ईश्वर का ध्यान करते हुए मुंह में दो लौंग रख लें। इसे कार्यस्थल पर पहुंचने तक मुंह में ही रखें। निर्धारित कार्यस्थल पर पहुंच कर उस लौंग को फेंक दें। ऐसा करने से आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा।

टाटा मोटर्स ने प्राइसिंग के साथ नेक्सन ईवी पोर्टफोलियो को नए अंदाज में पेश किया

मैक्स वैरिएंट्स की रेंज को बढ़ाकर 453 किलोमीटर तक किया
नेक्सन ईवी रेंज की कीमत अब आकर्षक 14.49 लाख रुपये से शुरू

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

भारत का प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माता, टाटा मोटर्स देश में नेक्सन ईवी के लॉन्च के तीन साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। कंपनी ने भारत के क्1 ईवी, नेक्सन ईवी पोर्टफोलियो को कीमतों में बदलाव और बेहतर रेंज के साथ नये अंदाज में प्रस्तुत करने की घोषणा की। ड्राइविंग और यूजर पैटर्न्स के आधार पर मिली जानकारी के साथ, नेक्सन ईवी मैक्स वैरिएंट्स की रेंज 453ङ किलोमीटर (एमआईडीसी) तक बढ़ाई गई है। यह बढ़ी रेंज 25 जनवरी, 2023 से लागू हो रही है। रेंज में यह बढ़ोतरी नेक्सन ईवी मैक्स के मौजूदा मालिकों को 15 फरवरी, 2023 से कंपनी की डीलरशिप्स पर एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड के माध्यम से प्रदान की जाएगी। कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में खूबियों से भरपूर नेक्सन ईवी मैक्स एक्सएम ट्रिम को लॉन्च किया। यह वैरिएंट 16.49 रुपये लाख की आकर्षक कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, आटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, आई-वीबीएसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपीङ), एलईडी डीआरएल और एलईडी टेल लैम्प्स के साथ प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, पुश बटनर स्टार्ट, डिजिटल टीएफटी इंस्ट्रूमेंट कलस्टर, स्मार्टवाच कनेक्टिविटी के साथ जेडकनेक्ट कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और रियर डिस्क ब्रेक्स से लैस होगा।

टॉप एंड ट्रिम, नेक्सन ईवी मैक्स एक्सजेड+ लक्स की नई कीमत 18.49 लाख रुपये रखी गई है। सम्पूर्ण नेक्सन ईवी श्रृंखला के लिए बुकिंग्स तुरंत आरम्भ हो रही है। नए वैरिएंट नेक्सन ईवी मैक्स एक्सएम की डिलीवरी अप्रैल 2023 से आरम्भ होगी। नेक्सन ईवी पोर्टफोलियो में नए बदलावों पर टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के हेड - मार्केटिंग, सेल्स और सर्विस स्ट्रैटेजी, श्री विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि, 'भारत की #1 ईवी, नेक्सन ईवी ने तीसरा सफल साल पूरा कर लिया है। इसे 40,000 से अधिक ग्राहकों का प्यार और भरोसा हासिल है और इसे 600 मिलियन किलोमीटर तक ड्राइव किया जा चुका है।

सोनी ने अल्ट्रा-वाइड ज़ूम लेंस को नए सिरे से परिभाषित किया

बेहतरीन इमेज क्वालिटी, उच्चतम और ऑटो फोकस परफॉर्मेंस

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सोनी FE 20-70mm F4 G (मॉडल - SEL2070G) के साथ लेंस की स्टैंडर्ड ज़ूम श्रेणी को फिर से परिभाषित कर रहा है, जो उल्लेखनीय रूप से कॉम्पैक्ट अल्ट्रा-वाइड 20-70 mm ज़ूम रेंज, हल्के फुल-फ्रेम लेंस, सम्पूर्ण ज़ूम रेंज में कांस्टेंट F4 एपर्चर का दावा करता है। असरदार G लेंस TM इमेज क्वालिटी, हाई स्पीड वाली सटीकता और ट्रैकिंग AF और अधिकतम गतिशीलता और ऑपरेबिलिटी के लिए एक स्मार्ट डिजाइन के साथ, यह नया लेंस ढेरों अलग-अलग तरह के क्रिएटर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। FE 20-70mm F4 G अलग-अलग तरह के कंटेंट को कैप्चर करने के लिए एकदम सही विकल्प है, जैसे व्लॉगिंग और मूवी प्रोडक्शन से लेकर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के स्टिल शॉट्स।

सोनी इंडिया के डिजिटल इमेजिंग हेड मुकेश श्रीवास्तव कहते हैं कि 'FE 20-70mm F4 G, लेंसों की स्टैंडर्ड ज़ूम कैटेगरी को नए सिरे से परिभाषित करेगा। यह लेंस 20 mm से 70 mm तक की अल्ट्रा-वाइड ज़ूम रेंज प्रदान करता है जो नए ज़माने के कंटेंट क्रिएटर्स को काफी वर्सटाइल, बढ़िया इमेजरी और उच्च-स्तरीय संचालन क्षमता प्रदान करेगा।' बेमिसाल अल्ट्रा-वाइड 20 mm से 70 mm ज़ूम रेंज और कांस्टेंट F4 एपर्चर सहित, FE 20-70mm F4 G खासतौर पर कॉम्पैक्ट, हल्के लेंस के साथ बेहतरीन ऑप्टिकल परफॉर्मेंस देता है, जिसके लिए Sony के नवीनतम लेंस डिज़ाइन और XD (एक्सट्रीम डायनामिक) लीनियर मोटर्स टेक्नोलॉजी का शुक्रिया। एक कॉम्पैक्ट मिररलेस बॉडी के साथ कंबाइंड, यह लेंस हर एक फोकल लंबाई पर तकरीबन किसी भी पोजीशन में शानदार इमेज क्वालिटी दे सकता है। यह कम से कम उपकरणों के साथ शूटिंग करने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। ज़ूम रेंज का अल्ट्रा-वाइड 20 mm अंत 16:9 या 2.35:1 एस्पेक्ट रेशियो के साथ वीडियो शूट करते समय वाइड एंगल व्यू बनाए रखना संभव बनाता है।

सयाजी इंदौर द्वारा आयोजित वाज़वान फूड फेस्टिवल के मौके पर

ब्लू लैगून में कश्मीर के व्यंजनों का आनंद

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

शहर के सबसे पसंदीदा ए-ला-कार्ट रेस्टोरेंट, ब्लू लैगून, ने 19 से 29 जनवरी तक कश्मीरी फूड फेस्टिवल 'वाज़वान' का आयोजन किया है। कश्मीर की हरी-भरी घाटियों के लजीज व्यंजन जैसे नुदरू, नून चाय, गुस्ताबा, मटन रोगन जोश, शुफ्ता आदि आपको खानपान के नए अहसास देंगे। श्री प्रसाद राव, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस, सयाजी इंदौर ने बताया कि 'कश्मीर केवल अपने मनोहर दृश्यों के लिए ही नहीं, बल्कि पाक कला के लिए भी धरती का स्वर्ग माना जाता है। इन व्यंजनों में इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मसालों का स्वाद और उनकी सुगंध धरती पर व्यंजनों के स्वर्ग का अनुभव प्रदान करती है। विश्वसनीय सुगंध, केसर, सूखे मेवे और गर्म मसालों से भरपूर कश्मीरी व्यंजन आपको बेहतर और यादगार अनुभव प्रदान करेंगे, जिसका आप हमेशा अधिक से अधिक आनंद उठाना चाहेंगे। ब्लू लैगून पूल साइड लक्ज़री डाइनिंग अनुभव के लिए काफी चर्चित है जिसमें लाइव संगीत और आपके पसंदीदा खानपान के साथ आपके बैठने की भव्य व्यवस्था है। पूरे शहर के मेहमानों के लिए, यहां वेजिटेरियन एवं नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह के ग्रिल, कबाब, भारतीय व्यंजन उपलब्ध हैं।

10.417 करोड़ डॉलर बढ़ा देश का खजाना, जानें कितना है गोल्ड रिजर्व

नई दिल्ली। एजेंसी

देश के विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी आई है। 13 जनवरी, 2022 को खत्म हुए सप्ताह में यह 10.417 अरब डॉलर बढ़कर 572 अरब डॉलर हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को कहा कि हाल के दिनों में किसी एक सप्ताह में यह सबसे अधिक वृद्धि है।

पिछले सप्ताह देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 1.268 अरब डॉलर घटकर 561.583 अरब डॉलर रह गया था। गौरतलब है कि अक्टूबर, 2021 में विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। वैश्विक घटनाक्रमों के बीच केंद्रीय बैंक के रुपये की विनियम दर में तेज गिरावट को रोकने के लिए मुद्रा भंडार का उपयोग करने की वजह से बाद में इसमें गिरावट आई थी। अक्टूबर 2022 में, विदेशी मुद्रा भंडार में एक सप्ताह के दौरान 14.721 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी।

9.078 अरब डॉलर बढ़ी एफसीए

आरबीआई के साप्ताहिक आंकड़ों के मुताबिक, कुल मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा माने जाने वाली फॉरेन करेंसी एसेट यानी एफसीए 13 जनवरी को खत्म हुए सप्ताह में 9.078 अरब डॉलर बढ़कर 505.519 अरब डॉलर पर पहुंच गई. डॉलर में बताई जाने वाली एफसीए में विदेशी मुद्रा भंडार में रखी यूरो, पाउंड और येन जैसी दूसरी विदेशी मुद्राओं के मूल्य में वृद्धि या कमी का प्रभाव भी शामिल होता है।

वाराणसी में बनेगा देश का दूसरा रिवर सीएनजी टर्मिनल, इन लोगों को होगा बड़ा फायदा

नई दिल्ली। एजेंसी

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुई सीएनजी बोट रैली खत्म हो गई है। काशी के नमो घाट पर इस रैली का आयोजन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने किया था। यहां केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश का दूसरा रिवर सीएनजी टर्मिनल काशी में बनेगा। यह गंगा किनारे रविदास घाट पर बनेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से जमीन सहित दूसरी औपचारिकताएं पूरी होते ही पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से कार्य शुरू कर दिया जाएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि इंडिया एनर्जी वीक 2023 का आयोजन होना है। यह भारत के जी-20 की अध्यक्षता के दौरान बेंगलुरु में 6-8 फरवरी 2023 तक 'ग्रोथ, कोलैबोरेशन, ट्रांजिशन' विषय के अंतर्गत किया जा रहा है।

वाराणसी में सीएनजी से तब्दील हुईं 580 नावें

उन्होंने कहा कि लोगों को ऊर्जा और सीएनजी के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से वाराणसी में सीएनजी बोट रैली का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर और वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध घाटों के जीर्णोद्धार और विकास जैसे अभूतपूर्व प्रयास महत्वपूर्ण हैं। पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री की चाह थी कि वाराणसी में नाव डीजल की जगह सीएनजी से चले। उन्होंने कहा, 'आज बताते हुई खुशी हो रही है कि वाराणसी में 580 नावें सीएनजी में तब्दील हो गई है। डीजल की तुलना में सीएनजी अधिक कुशल ईंधन होने के कारण नाविकों को काफी बचत होती है। सीएनजी डीजल की तुलना में 18 फीसदी ज्यादा माइलेज देती है। नाविक समुदाय ने इसका उपयोग कर अधिक रुपये की बचत की है।'

जल्द ग्रीन हाइड्रोजन से चलेगी नाव

पुरी ने कहा, 'वाराणसी में नाव अभी सीएनजी से चल रही हैं। वो समय जल्द आएगा, जब यहां की नाव ग्रीन हाइड्रोजन से चलती दिखेगी।' केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विश्वगुरु बनने की दहलीज पर खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन की बदौलत आजादी के 100वें वर्ष में इसके 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए और साल 2070 तक जीरो कार्बन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चार-आयामी रणनीति के माध्यम से कार्य कर रहा है।

एक करोड़ से ज्यादा हुए पीएनजी कनेक्शन

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएनजी (घरेलू) कनेक्शन 2014 में 22.28 लाख से बढ़कर 2022 में 1 करोड़ से अधिक हो गए हैं। सीजीडी कवर जिलों की संख्या 2014 में 66 से नौ गुना से अधिक बढ़कर 2022 में 630 हो गई है। भारत में सीएनजी स्टेशनों की संख्या 2014 में 783 से बढ़कर 2022 में 4900 हो गई है। इसी तरह देश के अंदर 2014 में 14 हजार किमी पाइपलाइन का विस्तार था। अभी 23 हजार किमी तक पाइपलाइन का विस्तार हो गया है और आने वाले समय इसे 34 हजार किमी तक ले जाने का प्लान है।

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अपनी रिपोर्ट ज्वेलरी डिमांड एंड ट्रेड लॉन्च की

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत में सोने के बाजार के अपने गहन विश्लेषण के साथ अपनी रिपोर्ट 'ज्वेलरी डिमांड एंड ट्रेड' लॉन्च की है। इस रिपोर्ट में भारत में पिछले सालों में उपभोक्ता के व्यवहार में आए परिवर्तन के बाद सोने के आभूषणों की मांग और महत्व का आकलन किया गया है। यह रिपोर्ट भारत में आभूषणों के वर्गीकरण पर रोशनी डालती है और सोने के आभूषणों के लिए क्षेत्रीय आय एवं लोगों की मांग का विश्लेषण करती है। इस रिपोर्ट में भारत से आभूषणों का निर्यात करने के लिए सबसे बड़े बाजारों और उद्योग के ठोस परिदृष्य को भी टटोला गया है।

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में क्षेत्रीय सीईओ, भारत, सोमसुंदरम पीआर ने कहा, ''भारत विश्व में सोने के बाजारों के लिए एक मजबूत स्तंभ है, और स्वर्णकारों के लिए दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। विवाहोत्सव और त्योहार आभूषणों की मांग को बल देते हैं, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्थिति वैश्विक कारोबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिससे सोने के साथ हमारा मजबूत सामाजिक-आर्थिक संबंध प्रदत्त होता है। समय के साथ हमने सोने को संजोने के लिए अनेक कारणों और खुशी के अवसरों का निर्माण कर लिया है। अकेले ब्राईडल ज्वेलरी का सेगमेंट बाजार के लगभग आधे हिस्से के बराबर है, और देष में सोने के आभूशणों का सबसे बड़ा उपभोक्ता ग्रामीण बाजार है।

दीर्घकाल में भारत में सोने के आभूषणों की मांग आर्थिक वृद्धि, आय में वृद्धि और संपत्ति के वितरण, तथा 'शहरीकरण की दर के साथ बढ़ेगी। सोने के साथ सांस्कृतिक संबंध मिलेनियल्स के बीच भी जारी रहेंगे या नहीं, यह देखना अभी बाकी है। यद्यपि यह संभव है कि मार्केटिंग और डिजिटल प्रगति इन-स्टोर अनुभवों को बदल सकते हैं और खरीदी करने की अलग तत्परता एवं क्षणों को प्रेरित कर सकते हैं, जो पारंपरिक कारणों के मुकाबले अलग हो सकते हैं, पर सोने के आभूषणों का आकर्षण मजबूत बने रहने की उम्मीद है। आभूषणों का निर्माण व निर्यात मजबूत बनाने के सरकार के केंद्र से अभिनवता की लहर आएगी, जो उच्च गुणवत्ता और कारीगरी द्वारा सोने के साथ संबंध को पुनः ताजा कर देगी, और भारत को विश्व का जौहरी बनने में मदद करेगी।''

केंद्रीय बजट में उद्योग संस्थानों में कौशल विकास के लिए बजट की मांग

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

उद्योग-संस्थान में कौशल की खाई को कम करने की दिशा में प्रयास किए जाने के लिए केंद्रीय शिक्षा बजट 2023 में प्रावधान किए जाने की मांग ग्रेट लर्निंग के फाउंडर और सीईओ मोहन लखमराजु करते हैं। 'बड़ी संख्या मेंयुवाओं को उद्योग के लिये प्रासंगिक कौशल से लैस करना भारत कीआर्थिक वृद्धि को आगे ले जाने का एक निश्चित तरीका है। मेरामानना है कि भारत के युवाओं के लिए किफायती उच्च शिक्षा तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अवसरों का विस्तार करना समय की मांग है ताकि उन्हें अत्याधुनिक कौशल विकसित करने के पर्याप्त अवसर मिल सकें। इस संदर्भ में, भारत सरकार आगामी वित्तीय बजट में कुछ पहलें कर सकती है- पहला, एडटेक कंपनियों को ऑनलाइन और हाइब्रिड डिग्री प्रोग्राम्स की पेशकश के लिये यूनिवर्सिटीज के साथ औपचारिक साझेदारी करने की अनुमति प्रदान करना, ताकि सरकार द्वारा निर्धारित ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके और दूसरा, अप स्किलिंग प्रोग्राम्स से जीएसटी हटाना, ताकि वे लोगों के लिये ज्यादा किफायती बन सकें। कार्यबल की नौकरी करने की संपूर्ण योग्यता को बढ़ाने के अलावा,यह उपाय हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा नवाचार करने को बढ़ावा देंगेऔर तकनीकी प्रगति को संभव बनाएंगे।'

एमएसडीई ने अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ साझेदारी की

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और उद्योगों में कुशल और भविष्य के लिए तैयार कार्य बल की आवश्यकता को पूरा करने हेतु एक मजबूत अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग फ्रेमवर्क बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) के साथ हाथ मिलाकर बहुत गौरवान्वित है।

साझेदारी के हिस्से के रूप में, हैदराबाद में बीडीएल फैसिलिटी में 250 से अधिक अप्रेन्टिसों को लगाया गया है, जहां 'अस्त्र' मिसाइल जैसी अत्याधुनिक एयर मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है। इस फैसिलिटी में, इन मिसाइलों के पांच कम्पोनेन्ट्स में से तीन बनाए जा रहे हैं। अप्रेन्टिसों को अन्य उद्योगों के साथ संपर्क प्राप्त करने के साथ-साथ फैसिलिटी में विभिन्न सेक्शन्स में ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे उन्हें सेक्टर में बेहतर विशेषज्ञता हासिल करने और सीएनसी ऑपरेटर और प्रोग्रामर, मशीनिस्ट, वेल्डर और टर्नर जैसे बड़ी पूंजी वाले ट्रेडों में प्रोग्रेसिव जॉब मार्केट का हिस्सा बनने में सक्षम बनाया जा सकेगा। एमएसडीई की एक टीम ने हाल ही में फैसिलिटी का दौरा किया और उन अप्रेन्टिसों के साथ बातचीत की। अप्रेन्टिसों ने भारत के युवाओं हेतु इस वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी में काम करने के लिए रास्ते खोलने, क्षमताओं को बढ़ाने और करियर की संभावनाओं में सुधार करने के लिए माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के प्रति आभार व्यक्त किया।

माननीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान की सराहना करते हुए, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी ने कहा, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और उद्योग राष्ट्र के विकास को गति देने में महत्वपूर्ण हैं और युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीडीएल सशस्त्र बलों के लिए गाइडेड मिसाइल सिस्टम और संबद्ध उपकरणों के उत्पादन के लिए अनिवार्य है। बीडीएल ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम (ध्ठश्ॐश्) के माध्यम से स्वदेशी, परिष्कृत और समकालीन मिसाइलों को बढ़ावा देने का बीड़ा उठाया है।

ब्रीथफ्रीयात्रा - भारत में रेस्पिरेटरी केयर की उपलब्धता बढ़ाते हुए

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

सिप्ला लिमिटेड ने नए साल की शुरुआत मरीजों की देखभाल पर केंद्रित रहते हुए की और अपना नया पेशेंट आउटरीच अभियान -ब्रीथफ्री यात्रा शुरू किया। यह अभियान लोगों को विभिन्न चैनल्स के माध्यम से अपने रेस्पिरेटरी स्वास्थ्य को पहचानने में मदद करने पर केंद्रित है ताकि क्रोनिक रेस्पिरेटरी समस्याओं, जैसे अस्थमा या सीओपीडी (क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिज़ीज़) की स्क्रीनिंग में मदद मिल सके। इस मुहिम पर निकलकर ब्रेदफ्री यात्रा तीन हफ्तों की अवधि में भारत में 300 से ज्यादा शहरों में पहुँचकर 60,000 से ज्यादा मरीजों को मदद पहुँचाएगी। डॉ. प्रमोद झंवर, एम.बी.बी.एस., डी.टी.सी.टी, एफ.सी.सी.पी, एम.सी.ए.आई. फिज़िशियन, छाती, दमा, क्षय, एलर्जी, ब्रोंकोस्कोपी, गहन चिकित्सा एवं निंद्रा रोग विशेषज्ञ के अनुसार, ''अस्थमा जैसी क्रोनिक रेस्पिरेटरी समस्याएं ठीक नहीं हो सकतीं, लेकिन समय पर निदान और मेडिकल इलाज द्वारा इन पर नियंत्रण पाना और सामान्य जीवन व्यतीत करना संभव है, परंतु छोटे शहरों के मरीजों को पर्याप्त मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं होतीं और वो अस्थमा जैसी बीमारियों के लक्षणों से अनजान होते हैं। इसके अलावा, इस बीमारी से जुड़ा सामाजिक कलंक अभी भी निदान या इलाज के मामले में एक बड़ी बाधा बना हुआ है, इसलिए जागरुकता का बढ़ाया जाना और ज्यादा जरूरी हो गया है। इसीलिए ब्रीथफ्री यात्रा जैसे अभियान मरीज को परीक्षण और डॉक्टर के परामर्श के साथ मेडिकल सहायता पहुँचाने के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। इससे वो अपनी बीमारी को बेहतर समझ सकेंगे, और उनके जीवन में वास्तविक परिवर्तन आएगा।'' 'केयरिंग फॉर लाईफ' के उद्देश्य से दिशा लेकर हमारा हर काम मरीजों पर केंद्रित होकर है। ब्रीथफ्री प्रोग्राम इस बात का अप्रतिम उदाहरण है कि कंपनी इन कार्यों को अंजाम कैसे देती है। विस्तृत मरीज सपोर्ट अभियानों में से एक, ब्रीथफ्री स्क्रीनिंग, काउंसलिंग, और इलाज के पूरे सफर में मरीजों को मदद पहुँचाता है।

लघु और मध्यम उद्योगों को डिजिटल करने मदद कर रहा नास्कॉम

सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस अब मप्र क्षेत्र में करेगा कार्य

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

पिछले कुछ सालों में देश में मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अपार विकास हुआ है। जिस प्रकार से भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरकर स्थापित हो रहा है, उसके अनुसार यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दुनिया की अर्थव्यवस्था में 500 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष का योगदान देगा। लेकिन इस प्रकार का विकास हमारी फैक्ट्री को स्मार्ट किए बिना संभव नहीं है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सुचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नास्कॉम के संयुक्त प्रयास से स्थापित सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस अब मध्यप्रदेश में अपने सेवाओ का विस्तार करेगा। लघु और मध्यम उद्योगों के पास डिजिटल समाधानों को लेकर जागरूकता, उन तक की पहुँच और उसे लागू करने के लिए आवश्यक पूँजी नहीं होती है। बड़े और लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्योगों में आधुनिक तकनीक को आत्मसात करने में आ रहे इस अंतर की वजह से ना सिर्फ एसएमई क्षेत्र को बड़ा नुकसान हो रहा है। नास्कॉम का सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस का उद्देश्य है भारत में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। यह सेंटर छोटे उद्योगों को आ रही चुनौती को सामने से स्वीकार करते हुए, उनका समाधान ढूँढने और एक बेहतर इकोसिस्टम बनाने और की ओर काम कर रहा है। नास्कॉम सीओएई के सेंटर हेड और सीनियर डायरेक्टर अमित सलूजा ने बताया कि नास्कॉम के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस ने भारत का सबसे बड़ा डीप-टेक कोलबोरेटिव इकोसिस्टम स्थापित किया है जिसमें उद्योग, स्टार्टअप, सरकारी तंत्र, शोध और शैक्षणिक संस्थाएं एक जगह पर मौजूद हैं। यह सीओई लघु उद्योगों और स्टार्टअप को साथ काम करने और कुछ नया इजात करने के लिए एक मंच प्रदान करता है जिससे उत्पादकता, दक्षता, और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एआई और आईओटी आधारित तकनीक से नवाचार लाया जा सके। उन्होनें बताया कि नैसकॉम सीओई में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग फोरम की भी शुरुआत की गई है जो की विशेष रूप से उन मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों के लिए है। इसके तहत उद्योगों के प्रमुखों के लिए मास्टरक्लास, क्षमता विकास कार्यशालाएं और डेमो के लिए कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। नास्कॉम सीओई उन लघु उद्योगों को भी मदद कर रहा है जो आधुनिक तकनीक और उपकरणों को इस्तेमाल करना चाहते हैं।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।